महामारी की मार
बीजेपी की हार

प्रस्तुत करते हैं

कोविड रिपोर्ट कार्ड
2024

A GUARANTEE CHECK OF TALL CLAIMS OF PANDEMIC

PC-PIC

8 बजे वाली बैठक की शुरुआत

8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को अचानक संबोधित किया, जिसमें दावा किया गया कि वह भारतीय नागरिकों से "एक विशेष अनुरोध करना" चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि उस दिन आधी रात होते-होते, सभी 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट अब वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। इसके स्थान पर, भारतीयों को इस विमुद्रीकृत (Demonetised) मुद्रा के नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए पचास दिन का समय मिलेगा, इस उम्मीद के साथ कि नकदी के रूप में कर रहित "काला धन" रखने वाले पकड़े जाएंगे।

उस समय प्रचलन में कुल नकदी का 86% हिस्सा 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों का था।

दावा:

सरकार ने दावा किया कि वे नोटबंदी के जरिए 3-4 लाख करोड़ रुपये का काला धन निकाल लेंगे।

वास्तविकता :

केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जून 2017 के अंत तक, विमुद्रीकृत (Demonetised) किए गए 1,000 और 500 रुपये के नोटों में से 98.96% आर.बी.आई को वापस कर दिए गए थे। फरवरी, 2019 में, तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया कि विमुद्रीकरण सहित सभी काले-धन विरोधी उपायों के माध्यम से 1.3 लाख करोड़ रुपये का काला धन बरामद किया गया है - जो अपेक्षित 3-4 लाख करोड़ रुपये से बहुत कम है। 2018 से पहले दो वर्षों में GDP की गिरती हुई दर के ज़िम्मेदार नोटबंदी और जीएसटी है। दिहाड़ी मज़दूरों की आमदनी जो नगदी में प्राप्त होती थी वह बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। लोगों के पास नकदी रुपए की कमी होने के कारण, वह ज़रूरतमंद चीज़ों पर भी खर्च करने में असमर्थ थे।

नोटबंदी, यह पहली और आख़िरी बार नहीं था जब पीएम मोदी ने रातों-रात देश को इस तरह से प्रभावित करने वाला फैसला लिया; रात 8 बजे की यह बैठक महामारी के दौरान भी जारी रही, फलस्वरूप देश के नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया।

कोविड-19 लॉकडाउन

भारत में पहला कोविड -19 का केस जनवरी 2020 में दर्ज किया गया, लेकिन मार्च 2020 तक केंद्र और राज्य सरकारों ने कोविड -19 को एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकट के रूप में देखने से इनकार किया । एक वैश्विक महामारी के बीच नागरिकों की चिंताओं को सम्बोधित करने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प का भव्य पैमाने पर स्वागत करने में व्यस्त थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश मे चुनी हुई सरकार को हटाने मे अपनी पार्टी की मदद कर रहे थे।

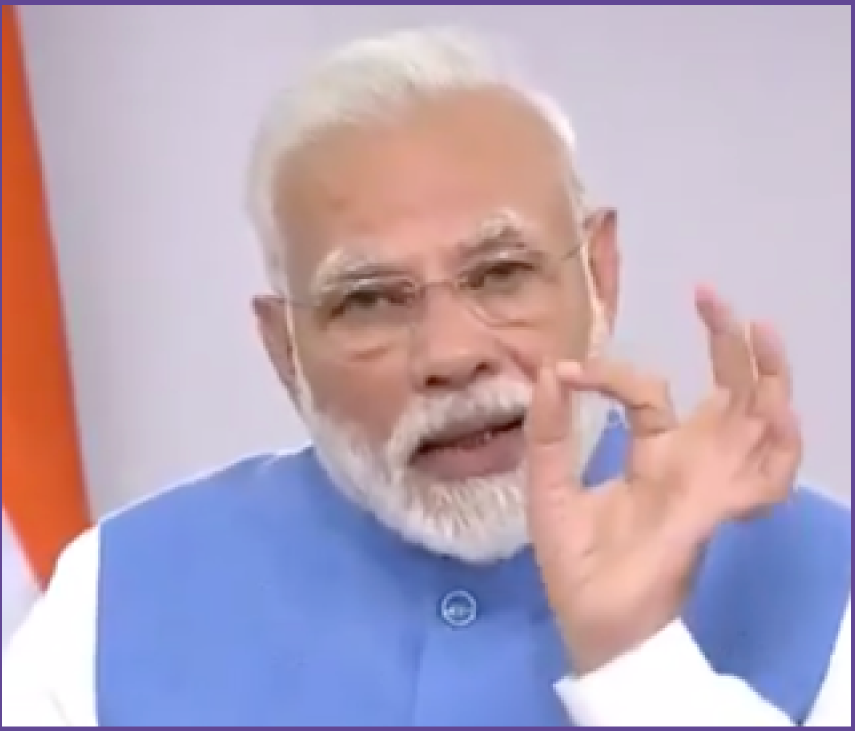

24 मार्च, 2020 को रात 8 बजे, प्रधानमंत्री ने, इस देश के 139 करोड़ लोगो को केवल 4 घंटे के नोटिस पर पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया ।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “5 अप्रैल की रात 9 बजे मुझे आपके 9 मिनट चाहिए। सभी लाइटें बंद कर दें, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाईल की फ्लैश-लाइट के साथ घर की बालकनी या दरवाज़े पर खड़े हो जायें”। (अप्रैल 2020)

“मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैं हर रोज़ गोमूत्र लेती हूँ। इसलिए अब, मुझे कोरोना के लिए कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ती और मुझे कोरोना नही है,”- बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर (मई 2021)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम को अचानक लागू करने और उसका उपयोग करने से उन लोगों का अपराधीकरण हो गया जो अपने अपने घरों से दूर फंसे हुए थे और जिन्हे आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों के कारण बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इतनी कठोर लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले उनकी जरूरतों पर ध्यान न देना सरकार की घोर विफलता थी।

दावा 01

भारत “सही समय पर सही निर्णयों के कारण बेहतर स्थिति में है”

(प्रधानमंत्री, जुलाई 2020)

जहाँ लॉकडाउन ने उच्च श्रेणी की सिर्फ़ गतिशीलता को प्रतिबंधित करके असुविधा पहुँचाई, वहीं कमजोर समुदाय के लोगों को बेरोज़गारी, आजीविका के नुकसान, आय की पूर्ण रूप से हानि इत्यादि जैसे अनेक संघर्षों के साथ जूझना पड़ा।

मार्च और जून 2020 के बीच, **एक करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों** को लॉकडाउन के बीचों बीच अपने गृह राज्यों में पैदल लौटने के लिए मजबूर किया गया।

- जबकि लॉकडाउन की घोषणा 24 मार्च 2020 को की गई थी, प्रवासियों, छात्रों, पर्यटकों आदि के वापस जाने के लिए ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें केवल 1 मई 2020 को शुरू की गई। इन **ट्रेनों में पानी और भोजन जैसी न्यूनतम सेवाएं भी उपलब्ध नहीं थीं**।
- यहाँ तक कि 2020 के अंत तक भी **1.5 करोड़ कर्मचारी बेरोजगार रहे**।
- बिना किसी पूर्व सूचना के लॉकडाउन के परिणामस्वरूप **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9% की गिरावट आई**।

कृत्रिम आपदा के चरण

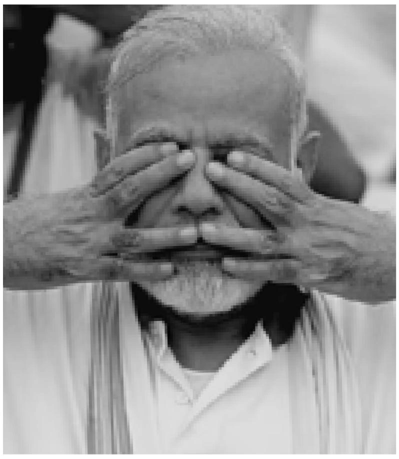

चरण 1: खण्डन

- 30 मार्च, 2020 तक, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर) कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार से इनकार कर रहे थे और परीक्षण रोगसूचक व्यक्तियों तक ही सीमित था।
- दूसरी ओर, मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों (एक साथ कई गंभीर बीमारियों) वाले रोगियों को डायलिसिस और कीमोथेरेपी जैसे नियमित आवश्यक उपचार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अस्पताल में प्रवेश और उपचार के लिए कोविड-19 नेगेटिव प्रमाणपत्र लाने के लिए मजबूर किया गया । एक सर्वेक्षण के अनुसार, **70% वरिष्ठ नागरिकों को महामारी के दौरान उचित स्वास्थ्य सुविधाओं तक की पहुँच नहीं थी**।
- बाद में, स्वास्थ्य मंत्रालय से गठित मंच (इंसाकॉग) द्वारा मार्च 2021 से आने वाली **दूसरी लहर के बारे में चेतावनी देने के बावजूद, सरकार में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया**।

चरण 2: सुचिन्तित अनभिज्ञता

- "हां, हम इसे स्टेज 3 कह रहे हैं - वायरस का सामुदायिक प्रसार । आधिकारिक तौर पर हम इसे नहीं कह सकते हैं - लेकिन यह चरण 3 की शुरुआत है," कोविड-19 अस्पतालों पर **एक टास्क फोर्स के संयोजक का एक बयान पढ़ें**।

यहाँ सवाल उठता है कि इसकी आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की गई ?

चरण 3: दोषारोपण का खेल

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी थी कि लगभग 30% मामले लक्षणरहित हो सकते हैं, इसके बावजूद सरकार ने लापरवाही कर केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तापमान की जाँच करने का आदेश दिया ।
- **आपदा में अवसर: मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सोची-समझी साज़िश**
  इन चेतावनियों को नकारते हुए, एन.डी.ए सरकार ने बार-बार सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने और दिल्ली में महामारी फैलाने के लिए तब्लीगी जमात को दोषी ठहराया, अर्थात् अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए तब्लीगी जमात का इस्तेमाल किया। हालांकि तब्लीगी जमात की मुस्लिम सभा तालाबंदी की घोषणा से पहले हुई थी।
- 5 अप्रैल, 2020 को **एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल जैसे अधिकारियों ने दावा किया** कि "अगर इस्लामिक संप्रदाय, तब्लीगी जमात ने दिल्ली में एक सभा का आयोजन नहीं किया होता, तो वायरस बहुत कम फैलता"। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत का नाम लिए बिना इस घटनाक्रम पर **स्पष्ट निराशा व्यक्त की**, साथ ही यह भी कहा कि कोविड मामलों का धार्मिक वर्गीकरण करना व्यर्थ है ।
- सरकार ने इस महामारी का फ़ायदा उठाते हुए आम जनता और शांतिपूर्ण रूप से विरोध करने वाले लोग, जिसमे विशेषरूप से युवा मुस्लिम छात्रों को आतंकवाद के आरोपों के तहत जेल में डाला। इसी प्रकार से उन्होंने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया।
- हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए) प्रवर्तित किए गए नियमों के साथ लागू किया गया है, लेकिन सरकार ने अभी एनआरसी के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। इससे जुड़े सभी बहादुर कार्यकर्ताओं को सलाम।

दावा 02

“मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक महामारी रहेगी, हम गरीबों की रक्षा करेंगे।”

(प्रधानमंत्री, संसद में, फरवरी 2022)

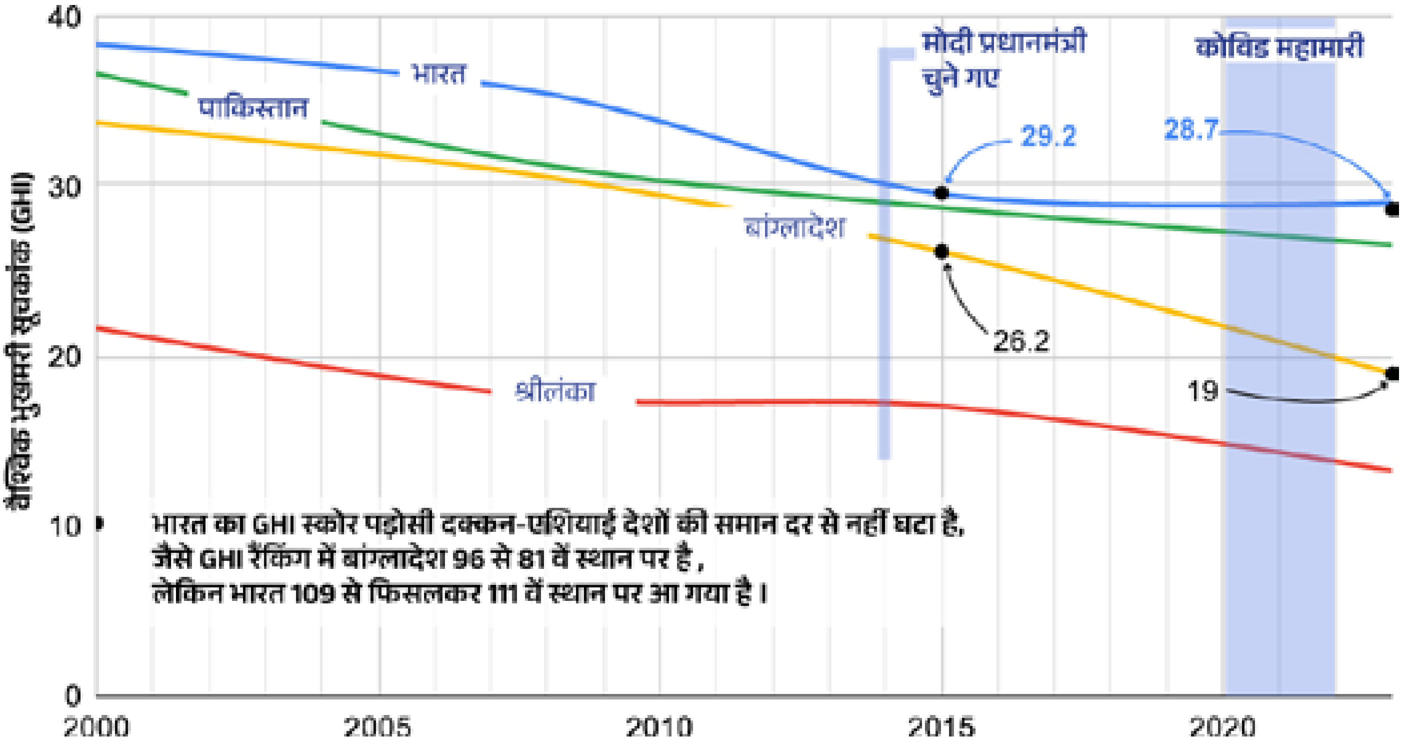

गरीबी और साझा समृद्धि 2022, विश्व बैंक के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि 2020 में COVID-19 **महामारी के कारण गरीबी में प्रवेश करने वाले लगभग 80% लोग भारत से थे**।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई) के अनुसार, पहली देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 में **12 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां खो दीं।**

2020 में गरीबी में प्रवेश करने वाले हर दस व्यक्तियों में से

आठ भारत से हैं ।

प्रभावी रूप से, महामारी के दौरान सबसे अमीर और भी ज्यादा अमीर हो गए और

गरीब और गरीब हो गए।

लॉकडाउन के दौरान
भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़कर

3 लाख करोड़ रुपये हो गई।

3,000,000,000,000

मार्च 2020 के लॉकडाउन के बाद से
शीर्ष 100 अरबपतियों की संपत्ति में इतनी वृद्धि हुई की

सबसे गरीब 13.8 करोड़ भारतीय लोगों में से प्रत्येक को 94,045 रुपये देने के लिए पर्याप्त है।

सबसे गरीब **20% परिवारों ने अप्रैल-मई 2020 में अपनी पूरी आय खो दी**।

2020-2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में **7.3% की गिरावट** आई।

मई 2020 के दौरान भारत की **बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई**, जो महामारी शुरू होने से पहले मार्च के मध्य में 7% से कम थी।

भाजपा सरकार ने मेहनतकश लोगों की मदद करने की बजाय, कई मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी कानूनों को पारित किया, और तो और इसके विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया।

भारत की
आय असमानता
अब ब्रिटिश राज से भी
बदतर हो गई है।

-विश्व असमानता लैब रिपोर्ट के अनुसार

दावा 03

“(भारत ने) कोरोनो वायरस पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करके विश्व को, सम्पूर्ण मानवता को एक बड़ी त्रासदी से बचाया है”

(प्रधानमंत्री, विश्व आर्थिक मंच पर, 28 जनवरी, 2021)

2021 में विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को सम्बोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत न केवल कोविड -19 संकट को हराने में कामयाब रहा, बल्कि सबसे बुरा होने की भविष्यवाणियों के बावजूद, इस प्रक्रिया में उसने 150 से अधिक देशों की मदद भी की।

किस पर नियंत्रण, महामारी या लोगों पर ?

- “हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क” द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2020 और जुलाई 2021 के बीच कोरोना वायरस महामारी के दौरान, सरकारी अधिकारियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने और अतिक्रमण हटाने के लिए भारत में लगभग **257,000 लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया**।
- ‘राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो’ (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में **हर 10 मिनट में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपराध का सामना करना पड़ा**, यानी 2020 में कुल 50,291 मामले दर्ज किए गए, जिसमे पिछले वर्ष से 9.4% की वृद्धि हुई है।
- भारत में प्रवासी श्रमिकों पर कोरोनो वायरस से लड़ने के लिए **कीटाणुनाशक का छिड़काव किया गया**।
- लगभग **55% भारतीयों को लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा पीटे जाने का डर था**, और उस अवधि में पुलिस की कार्रवाई पहले से ही वंचित समूहों जैसे “गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर निश्चित रूप से अधिक कठोर थी”।

लोगो की आप-बीती

"महामारी के दौरान, मुझे वन और पुलिस अधिकारियों द्वारा बार-बार परेशान किया गया। मुझे पीटा गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर मैंने दोबारा मुआवज़े का अनुरोध किया तो उन्होंने मुझे फर्जी कानूनी मामलों में फंसाने की धमकी दी" ~ ***देवकलिया, सोनभद्र, वनवासी समुदाय***

"2020 में, महामारी के दौरान, वन और पुलिस अधिकारियों ने मेरी जमीन को बरबाद कर दिया और मुझे खेती करने से रोक दिया। उन्होंने मेरी झोपड़ी भी नष्ट कर दी"

~ कुँवर, सोनभद्र, वनवासी समुदाय

जुलाई 2021 में, जब हम धान की खेती कर रहे थे, वन अधिकारियों की एक टीम आई और हमारे खेत और आसपास की हर चीज़ को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया और मेरी धान की नर्सरी बर्बाद कर दी. मुझे अपने घर से अपना सामान ले जाने का कोई समय नहीं दिया गया। अधिकारियों द्वारा मेरा घर ढहाने से मेरा 50,000 रुपये का सामान नष्ट हो गया।" ***~ राजकुमार, चंदौली , वनवासी समुदाय***

"जब लॉकडाउन हटा दिया गया, मैंने वेंडिंग फिर से शुरू कर दी, लेकिन पुलिस और एमसीडी अधिकारियों ने मुझे परेशान किया और मुझे काम करने की अनुमति नहीं दी। मार्च 2023 को, जब पुलिस ने मुझे वेंडिंग करते देखा तो पुलिस ने मेरी पिटाई की। मैंने उनसे कहा कि मैं उपवास कर रहा हूं और कुछ दया दिखाऊं। उन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाया और मुझे पीटते रहे। उनकी पिटाई के परिणामस्वरूप मेरे पैर की हड्डियाँ टूट गईं और मुझे इलाज कराना पड़ा। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं. कोविड-19 के दौरान, मैंने जीवित रहने के लिए 2,50,000 रुपये का ऋण लिया।"

" ***~ इमरान, दिल्ली से स्ट्रीट वेंडर समुदाय***

"महामारी ने मेरी आय को अत्यधिक प्रभावित किया है और मेरा आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। मुझ पर 10,00,000 रुपये का कर्ज है और मैं इसे चुकाने में सक्षम नहीं हूँ।" ***~ हीना, स्ट्रीट वेंडर समुदाय***

दावा 04

“देश में कोविड-19 महामारी से अब तक 5.33 लाख मौतें हो चुकी हैं; ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई।”

(फरवरी 2022)

हाल ही में 19 अप्रैल 2024 को, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने “**सभी की भलाई सुनिश्चित की और कोविड महामारी के दौरान ‘राष्ट्र पहले’ की भावना के साथ काम किया**”।

वास्तव में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पहली और दूसरी लहर के बीच 47 लाख से अधिक मौतें हुईं, जो दुनिया भर मे महामारी से मरने वालों की संख्या मे सबसे अधिक थी।

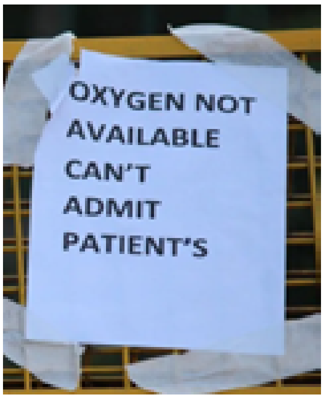

दुनिया भर में कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है।

हालाँकि, भारत सरकार के अनुसार, भारत में केवल 4.8 लाख लोगों की मृत्यु हुई - जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान का लगभग दसवां हिस्सा है।

अभी तक भारत एक लौता ऐसा देश है जिसने इतने बड़े पैमाने पर कोविड-19 से हुई अधिकांश मौतों की जानबूझकर गिनती नही की। इससे हमें यह मालूम होता है की झूठ और गलत सूचना ही इस सरकार की राजनीति है ।

सरकार ने इस अनुमानित संख्या पर पहुँचने के लिए **विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया**। हालाँकि,जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों की तुलना 2020 की पहली लहर से होने वाली सभी मौतों को नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सी.आर.एस) द्वारा दर्ज की गई संख्या से की गई , तो वे लगभग पूरी तरह से मेल खाते थे।

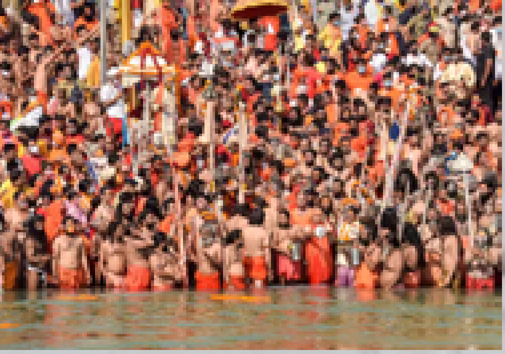

कुंभ मेला- २०२१, हरिद्वार और भाजपा रैली, पश्चिम बंगाल

मिलिए कोरोना के सुपरस्प्रेडर से

"कोरोना से जंग जीतने के लिए अनुशासन जरूरी है। आपके साहस, धैर्य और अनुशासन से देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हम मिलकर स्थितियां बदल देंगे।" (प्रधानमंत्री मोदी, 20 अप्रैल 2021)

- लेकिन इस बयान से ठीक तीन दिन पहले, **प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में हजारों उपस्थित लोगों के साथ एक विशाल राजनीतिक रैली की**, जहाँ उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्थानीय चुनावों में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही थी। "मुझे हर दिशा में, केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं! आप अद्भुत हैं!" (प्रधानमंत्री मोदी, 17 अप्रैल, 2021)। **उस दिन, भारत में 234,692 नए कोरोना वायरस मामलों की पुष्टि हुई** - जो जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत से इसकी **दैनिक संख्या** से 20 गुना अधिक थे।

- "जबकि चिकित्सा जगत लोगों को अनिवार्य कोविड मानदंडों को समझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, **प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कोविड मानदंडों को हवा में उड़ाते हुए बड़ी राजनीतिक रैलियों को सम्बोधित करने में संकोच नहीं किया**,"– इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. दहिया ने कहा ।

- सरकार ने बढ़ती हुई दूसरी लहर के बीच अप्रैल 2021 में कुंभ मेले की अनुमति दी। आसमान छूते कोविड केस की संख्या और मरीज़ों को ऑक्सीजन की कमी के साथ, सरकार को इतनी बड़ी धार्मिक सभा आयोजित करके अपने एजेंडे को उजागर करने और बहुसंख्यकों को खुश करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इस घटना के बाद कोविड-19 मामलों के और अधिक नियंत्रण से बाहर होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। **कुंभ मेला जल्द ही एक सुपरस्प्रेडर उत्सव बन गया, जिसने कोविड-19 महामारी को और भी बदतर बना दिया**।

- 30 मार्च 2021 को नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल ने कहा, "देश में वर्तमान कोरोना वायरस की स्थिति बढ़ते हुए मामलों के साथ **बद से बदतर होती जा रही है** और रुझान बता रहे हैं कि वायरस अभी भी बहुत सक्रिय है"। यह जानने के बावजूद, भारत सरकार **हरिद्वार कुंभ मेले** के आयोजन के लिए आगे बढ़ी, यहाँ तक कि इस आयोजन के **सुपर-स्प्रेडर** बनने की चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी के किनारे कोविड पीड़ितों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया गया

दावा 05

“आत्मनिर्भर भारत ने 60 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में अद्वितीय भूमिका निभाई”

(केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए, 24 दिसंबर 2023)

दिल्ली की एक रिपोर्ट में जनसुनवाई के हवाले से पता चला कि **86 स्ट्रीट वेंडर (95.6%) ने बताया कि महामारी ने उनकी कमाई पर भारी प्रभाव डाला, जबकि 83.34% (90 में से 75 स्ट्रीट वेंडर) को महामारी के कारण अपनी आय में 50% की कमी का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित स्ट्रीट वेंडरों को 75% से भी ज़्यादा की भारी कटौती का सामना करना पड़ा।**

महामारी के कारण अपनी आय में >50% की कमी

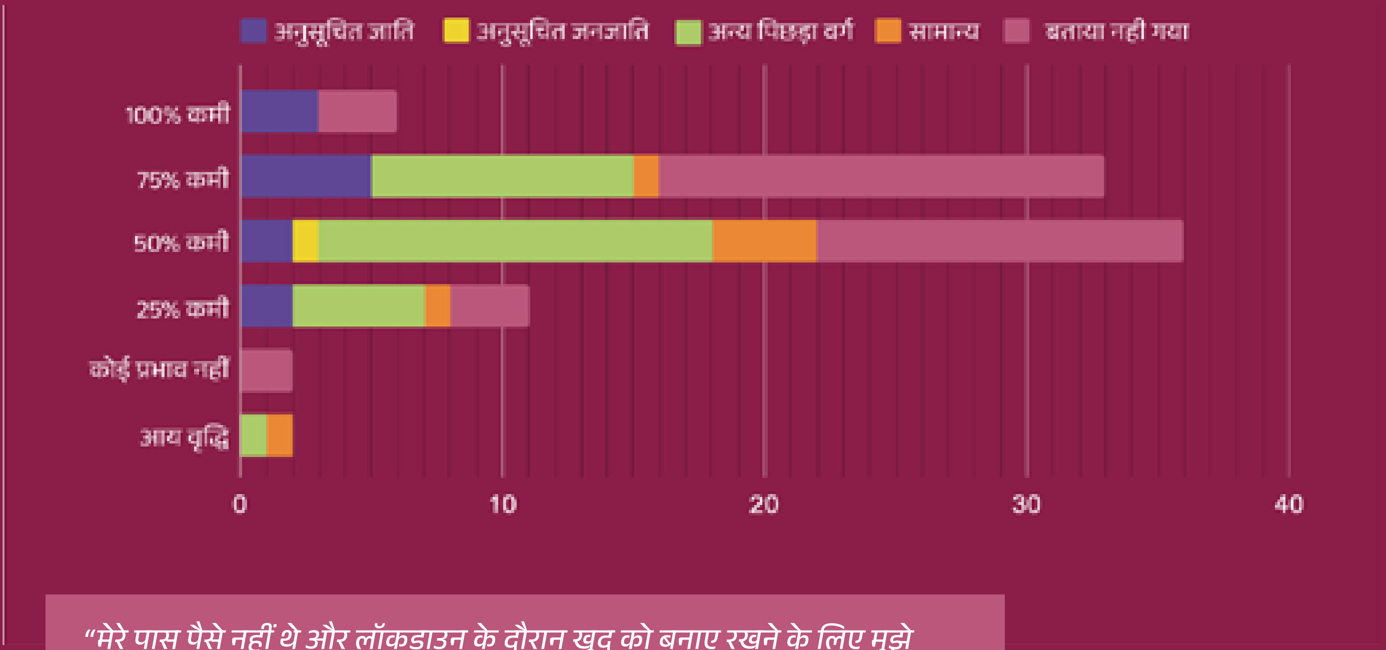

*“मेरे पास पैसे नहीं थे और लॉकडाउन के दौरान खुद को बनाए रखने के लिए मुझे 4,00,000 रुपये का कर्ज लेना पड़ा। आय में कमी के कारण, मैं यह राशि चुकाने में समर्थ नहीं हूँ,” –**राम चरण, ज्वाला नगर, दिल्ली से एक स्ट्रीट वेंडर***

*“लॉकडाउन के दौरान, मेरे बेटे ने साहूकारों से 1,50,000 रुपये का कर्ज लिया। आय की हानि के कारण वह यह राशि चुकाने मे असमर्थ था। उसे साहूकारों के लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जिस कारण वह बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए, मुझे 1,00,000, रुपये का एक और कर्ज लेना पड़ा जिसका भुगतान भी हम नही कर पा रहे हैं,”– **शांति देवी, कालकाजी, दिल्ली से एक 65 वर्षीय स्ट्रीट वेंडर***

> *“महामारी से पहले मैं सब्जियाँ बेचकर रोजाना 1,000 रुपये कमाती थी। अब मैं मुश्किल से 200 रुपये कमा पाती हूँ,”*
> ***–धन्वंती , ज्वाला नगर, दिल्ली की एक स्ट्रीट वेंडर***

महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा के खर्च का वित्तपोषण के साधन

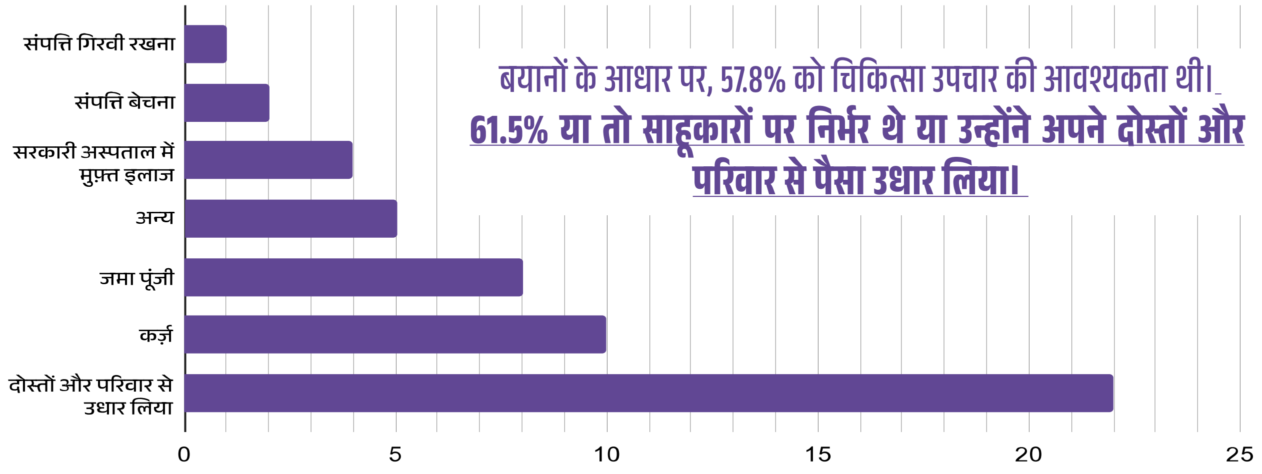

90 स्ट्रीट वेंडर में से **73 (81%) ने प्रकट किया कि वे महामारी के बाद से कर्ज में डूबे हुए हैं।** आधे विक्रेता 50,000 रुपये से अधिक के कर्ज में हैं और 22% विक्रेता 1 लाख रुपये और उससे अधिक के कर्ज में हैं।

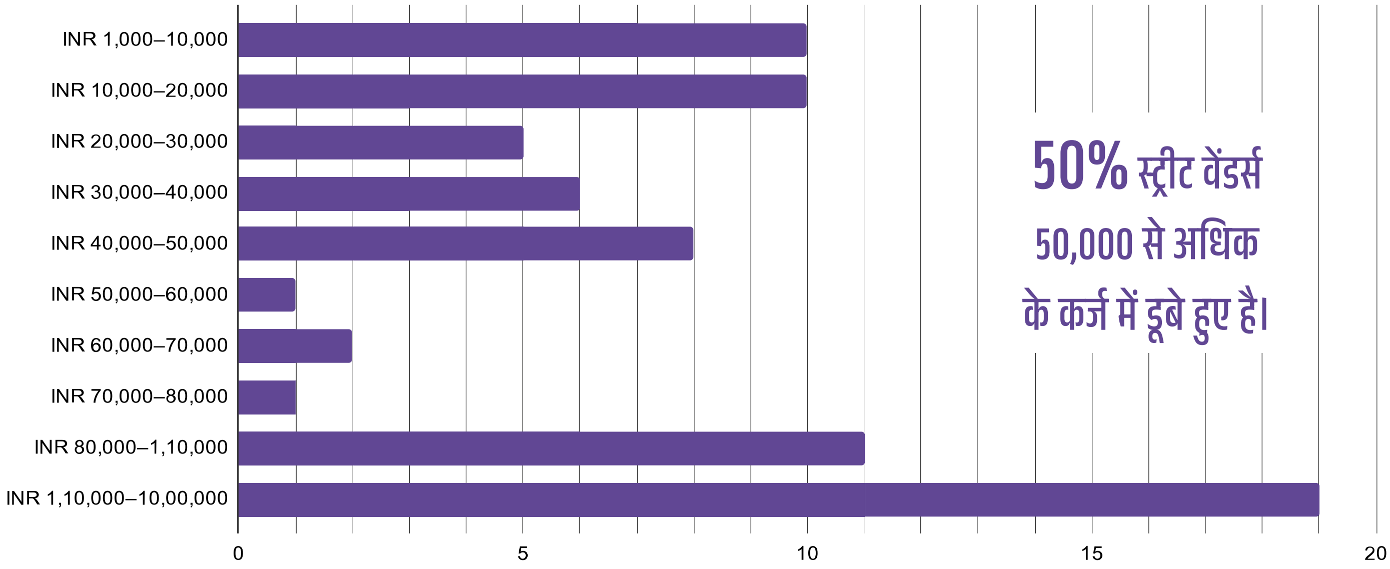

आत्मनिर्भर भारत ?

12 मई 2020 को, देशव्यापी लॉकडाउन के 49वे दिन, प्रधानमंत्री ने **आत्मनिर्भर भारत अभियान** को हरी झंडी दिखाई, और “भारत की जीडीपी के 10% के बराबर - 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज” की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि महामारी के कारण मौजूदा “वैश्विक व्यवस्था” के बिगड़ने से भारत को उस जिम्मेदारी को पूरा करने का “अवसर” मिला है और इसका लाभ उठाने का एकमात्र तरीका ‘आत्मनिर्भर भारत’ है।” **प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 33 मिनट के भाषण का लगभग आधा समय आत्मनिर्भर भारत के अपने दृष्टिकोण को उजागर करने में बिताया।**

उनके 395 वादों में से 41 असंगठित क्षेत्र के लिए थे। **इनमें से 16 सीधे तौर पर श्रम संहिताओं को कमजोर करने के लिए बनाए जाने वाले नीतिगत सुधारों से जुड़े थे।** केवल 25 वादे असंगठित क्षेत्र को दिए जाने वाले लाभों पर केंद्रित थे।

दावा 06

पीएम स्वनिधि: लाभार्थियों को बिना कुछ गिरवी रखे कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने वाली एक योजना।

14 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सम्बोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में स्ट्रीट वेंडर्स के उत्थान के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए मोदी ने कहा, **"मोदी गरीबों और मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।"**

मोदी ने जोर देते हुए कहा कि "मेरा ध्यान 'जनता के कल्याण के माध्यम से राष्ट्र का कल्याण करना', भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से खत्म करना, और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।"

स्ट्रीट वेंडर के एक वर्ग को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें आवेदन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा था। हालांकि स्ट्रीट वेंडर के एक वर्ग को ऋण प्राप्त हुआ, दूसरों को अपने ऋण स्वीकृत कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। स्ट्रीट वेंडर का एक अन्य वर्ग अभी भी अपने ऋण की अदायगी की प्रतीक्षा कर रहा है।

ज्वाला नगर के एक स्ट्रीट वेंडर ने जनसुनवाई में कहा, **"मैंने 10,000 रुपये के पीएम स्वनिधि ऋण के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक राशि नहीं मिली।"**

'लाभार्थियों' की राजनीति: कौन झूठ बोल रहा है- वित्त मंत्री, आवास मंत्री या आँकड़े?

पीएम ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की थी। फरवरी 2022 में जारी उनकी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर की पहचान करने में दो साल लग गए।

5 दिसंबर 2023 को, मंत्रालय ने कहा कि योजना के लाभार्थियों में **कुल 56.58 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं, और ठीक दो महीने बाद, फरवरी 2024 में, वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में गर्व से घोषणा की कि इस योजना से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हुए हैं।**

यहाँ यह सवाल पूछने की जरूरत है कि ये आंकड़े कहां से आए: 2022 से 2024 तक दो साल की अवधि में 30 लाख अतिरिक्त लोगों को इस योजना से लाभ हुआ, जबकि मंत्रालय को स्ट्रीट वेंडर की कुल संख्या की पहचान करने में ही दो साल लग गए। इससे पता चलता है की सरकार के आँकड़े का कोई मेल नहीं है तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? वित मंत्री, आवास मंत्री या फिर खुद आँकड़े ?

दावा 07

“भारत न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करेगा, बल्कि उनसे आगे निकलकर पर्यावरणीय क्षरण को रोकेगा, और इसे उलट भी देगा।”,

(प्रधानमंत्री मोदी, ‘क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट’, जनवरी 2021)

प्रधानमंत्री मोदी “वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र को अनुमति देना दुनिया के चौथे सबसे बड़े भंडार वाले देश के संसाधनों का ताला खोलना है” (जून, 2020)

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार ने कोविड लॉकडाउन-प्रेरित संकट से आर्थिक पुनरुद्धार के नाम पर, खनन क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाया। वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र के निवेश को अनुमति देने के लिए **41 कोयला ब्लॉकों की ऑनलाइन नीलामी शुरू की गई**।

इस संकट काल में तीन कानूनों में संशोधन करके और खानों की व्यावसायिक नीलामी की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित करके खनन सुधारों को सुविधाजनक बनाया गया, जो जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं।

ऐसे समय में जब दुनिया भर में ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले को गैस में बदलने के लिए 20,000 करोड़ का निवेश करेगा। दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा निर्यातक बनने के लक्ष्य के साथ-साथ, कोयला खनन का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। निजी लाभ के लिए खोली जा रही इन कोयला खदानों में से कई खदानें घने वन क्षेत्रों में हैं जो जैव विविधता से समृद्ध हैं और भारतीय संविधान की अनुसूची ‘V’ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए) अधिसूचना 2020 का प्रारूप

23 मार्च को, महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी 'थाली बजाओ' सार्वजनिक आह्वान में प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए "जनता कर्फ्यू" के बाद, सरकार ने कानून की किताबों से मौजूदा पर्यावरण संरक्षण को कमजोर करने के प्रयास में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2020 के मसौदे को उस समय जारी किया, जब लोग लॉकडाउन प्रतिबंधों और महामारी से उत्पन्न हुई अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। पर्यावरण आंदोलनों के व्यापक अभियान और अदालतों के हस्तक्षेप के कारण, कुछ महीनों के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 17,00,000 (1.7 मिलियन) आपत्तियाँ भेजी गईं।

कुछ ही महीनों के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 17 लाख आपत्तियाँ भेजी गईं

अनुमतियों की मंज़ूरी का बंदर-बाँट

7 अप्रैल, 2020 को एक ही दिन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घने जंगलों, बाघ अभयारण्यों, वन्यजीव अभयारण्यों, वन्यजीव गलियारों, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली 31 परियोजनाओं की सिफारिश की। वन सलाहकार समिति ने भी उसी महीने में अंधाधुंध तरीके से परियोजनाओं को मंजूरी दे दी और जंगल के विशाल भूभाग को परिवर्तित करने की अनुमति देने के लिए वन मंजूरी दे दी। महामारी संकट के बीच, 191 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने का इरादा रखने वाली 'विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति' ने 15 ऑनलाइन बैठकों में प्रति परियोजना औसतन 10 मिनट खर्च किए। अतिरंजित सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाओं को अप्रैल के अंत में महामारी के चरम और प्रवासी श्रमिक संकट की सबसे खराब अवधि के दौरान मंजूरी दी गई थी।

> महामारी संकट के बीच 191 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने का इरादा रखने वाली विशेषज्ञों की मूल्यांकन समिति ने 15 ऑनलाइन बैठकों में प्रति परियोजना औसतन 10 मिनट खर्च किए।

दावा 08

“महामारी से लड़ने के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। हमारे साथी नागरिकों को उचित देखभाल मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हम स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे में वृद्धि कर रहे हैं।”

(प्रधानमंत्री मोदी, 16 जनवरी 2022)

महाराष्ट्र से आई एक रिपोर्ट मे कहा गया है कि “भारत में कई निजी अस्पतालों, विशेष रूप से कॉर्पोरेट अस्पतालों ने महामारी को अधिकतम लाभ कमाने के अवसर के रूप में देखा, जैसा कि मीडिया में व्यापक रूप से बताया गया है। कुछ कोविड-19 के मरीजों से कथित तौर पर **इलाज के लिए प्रतिदिन का 50,000 से 1 लाख रुपये तक का शुल्क लिया गया**।”

राज्य की एक अन्य रिपोर्ट मे कहा गया है कि “77 कोविड-19 गंभीर देखभाल प्रकरणों (क्रिटिकल केयर एपीसोडस) के एक उपसमूह के अस्पताल में भर्ती होने और दवाइयों पर प्रतिदिन होने वाले खर्च के विश्लेषण से पता चला कि **औसत दैनिक चिकित्सा बिल आधिकारिक दरों के अनुसार होने वाले खर्चों की तुलना मे 400% से 500% अधिक था।** इससे पता चला कि किफायती चिकित्सा बिलों के नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ”

“दवाओं की कीमत भी अत्यधिक बढ़ गई थी। **श्रीनगर में, रेमडेसिविर को 6,000 रुपये की सामान्य दर के मुकाबले 36,000 रुपये तक में बेचा जा रहा था**।”

मरीजों को लगभग 10-15 किमी की दूरी तक ले जाने के लिए, **मुंबई में एम्बुलेंस मालिकों ने 30,000 रुपये तक का शुल्क लिया। पुणे में महज 7 किमी दूर अस्पताल जाने के लिए एक मरीज को 8,000 रुपये खर्च करने पड़े। कोलकाता में, मरीजों से 5 किमी की दूरी के लिए 8,000 रुपये तक का शुल्क लिया गया, जबकि हैदराबाद में, 10 किमी तक की दूरी के लिए परिवहन शुल्क 5,000 से 10,000 रुपये के बीच था।**

Rs. 8000-18000 प्रतिदिन (आधिकारिक दरों के अनुसार)

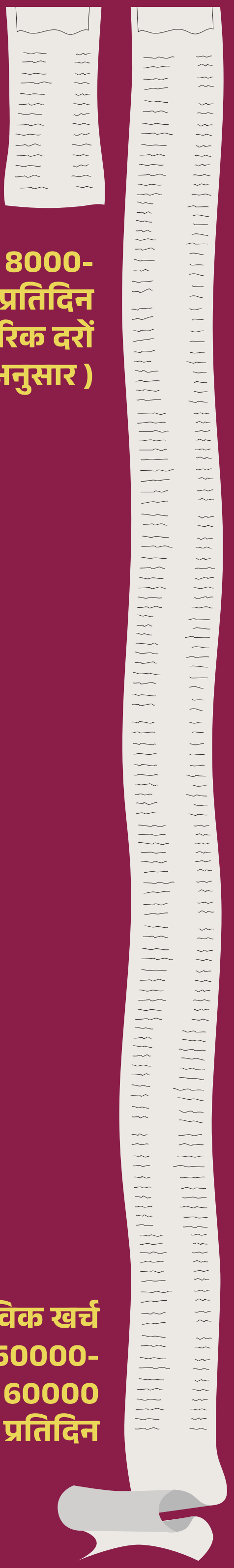

वास्तविक खर्च Rs. 50000-60000 प्रतिदिन

आई.सी.एम.आर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों की संख्या का विवरण

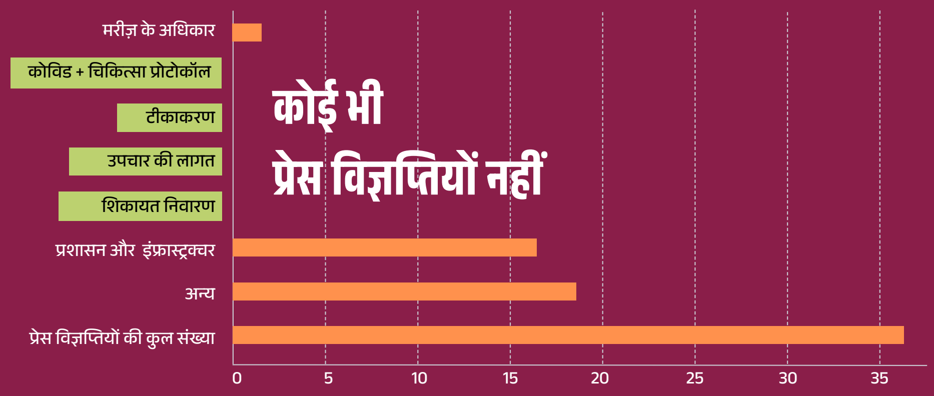

“2020 और 2021 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर) द्वारा जारी की गई कोविड-19 से संबंधित अधिकांश अधिसूचनाएं प्रशासन और बुनियादी ढाँचे से संबंधित थीं। **स्वास्थ्य संबंधी 38 अधिसूचनाओं में से 16 प्रशासन और बुनियादी ढाँचे से संबंधित थीं। एक अधिसूचना 'मरीज़ के अधिकारों' पर थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उपचार की लागत, कोविड -19 और चिकित्सा प्रोटोकॉल, शिकायत निवारण और टीकाकरण से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की**।”

“सभी राज्यों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य वैधानिक स्वास्थ्य निकायों द्वारा तैयार किए गए 'कोविड-19 के लिए नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल' (क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल) का पालन किया। **पहला संस्करण 17 मार्च 2020 को प्रकाशित हुआ था और केंद्र सरकार जनवरी 2022 तक कोविड -19 प्रबंधन के लिए अपनी रणनीति को संशोधित करती रही**।”

“**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली ने केवल एक अधिसूचना जारी की जिसे 2020 में चिकित्सा प्रोटोकॉल में वर्गीकृत किया जा सकता है**। 7 जून 2020 को जारी अधिसूचना में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के लिए कोविड-19 संक्रमित और गैर-संक्रमित दोनों रोगियों को दिशानिर्देश दिए गए। हालाँकि, परिपत्र (सर्कुलर) में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए उपचार योजना के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

“**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली ने उपचार की लागत, उपचार की कीमतों की कैपिंग, ऑक्सीजन, परीक्षण किटों की कीमतों आदि के संबंध में 2020 में तीन और 2021 में दो परिपत्र (सर्कुलर) जारी किए।”** गौरतलब है कि सभी अधिसूचनाएँ कीमतों में संशोधन से संबंधित थीं परंतु फिर भी बड़ी जनसंख्या के खर्च वहन के सामर्थ्य को नकार दिया।

विज्ञान आधारित दृष्टिकोण ?

कई अस्पतालों ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करना शुरू कर दिया। पहले से ही उपचारित मरीज से प्लाज्मा लेने से न केवल उत्पात और उनका शोषण हुआ, बल्कि बाद में यह पाया गया कि प्लाज्मा थेरेपी अप्रभावी थी और इसकी कोविड -19 के इलाज में कोई भूमिका नहीं थी। **17 नवम्बर 2020 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा प्लाज्मा थेरेपी के अनुचित उपयोग को सम्बोधित करने के लिए एक परामर्शी (एडवाईज़री) जारी की गई**। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी गंभीर कोविड -19 वाले लोगों के इलाज में अप्रभावी थी।

ये साक्ष्य सहित कुछ उदाहरण मात्र हैं, सूची बहुत लम्बी है। विज्ञान कहाँ था? नागरिकों को उचित देखभाल प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचा कहाँ था?

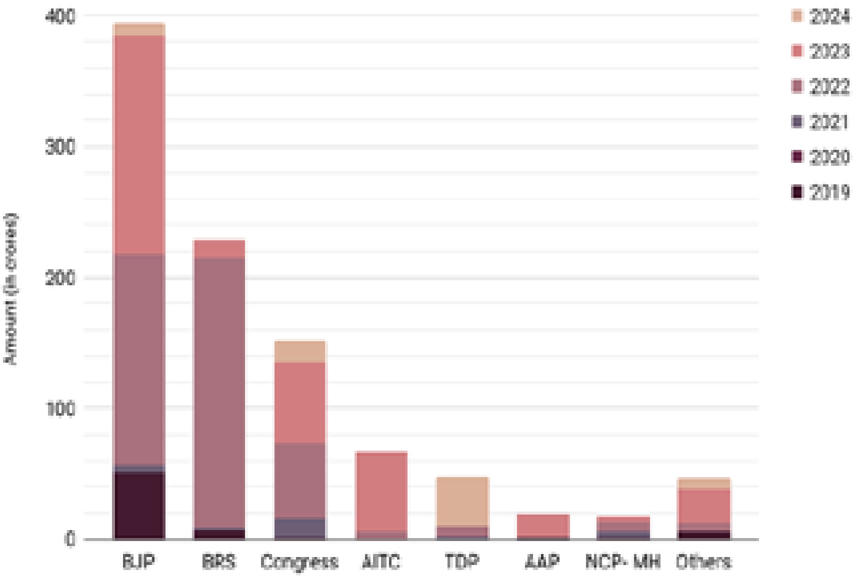

फार्मा कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान किये गये चुनावी बॉन्ड

किसने अपना ख़ज़ाना भरा ?

जैसे ही भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर अनिच्छा से चुनावी बॉन्ड के आँकड़े साझा किए, तो यह स्पष्ट हो गया कि संघ स्तर पर सत्ता में पार्टी (यानी, भारतीय जनता पार्टी) ने दवा कंपनियों, यहाँ तक की जो महामारी के दौरान टीकों और अन्य आवश्यक दवाओं के निर्माण में लगे हुए थे, से पैसे लेकर अपने खजाने भरे थे। इन योगदानकर्ताओं में वे कंपनियाँ शामिल हैं, जिनकी दवाएँ चिकित्सीय परीक्षण में भी पास नहीं हुईं।

जब सभी कस्बों और शहरों में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे, तब स्वास्थ्य और दवा कंपनियों ने 900 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे।

कोविड -19 के बारे में [भाजपा के 2024 घोषणापत्र]() में खोजने पर, हमें केवल 3 परिणाम मिले - जिसमे से केवल एक दावा है और अन्य 2 उल्लेख केवल महामारी युग का संदर्भ हैं !

दावा 09

“वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 देशों को 30 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके और दवाओं सहित अन्य सहायता प्रदान की”

कथन-1

“वैश्विक चुनौतियों और कोविड महामारी जैसी घटनाओं के बावजूद, हमारी आर्थिक नीतियों ने बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजत किए हैं।”

कथन-2

“हमने वैश्विक अस्थिरता और कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भारत को फ़्रैजाइल-5 (फ्रैजिल-5) से विश्व की 5वी आर्थिक शक्ति बनाने में सफलता हासिल की है।”

वास्तविकता

ऐसा कहा जा रहा है की भारत ने वैक्सीन कूटनीति में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और दुनिया भर के कई गरीब देशों को टीके उपलब्ध करा कर वाह-वाही बटोरी, फिर भी इन सबके बावजूद ये अस्पष्ट है की इसका असली लाभार्थी कौन था। हमारी नज़रों के सामने स्पष्ट हो रहा है की लाभार्थी कौन थे। अदार पूनावाला-और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी को 52 करोड़ रुपये का योगदान दिया। क्या यह कोविशील्ड नामक ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोविड -19 वैक्सीन के स्थानीय स्तर पर विनिर्माण के लिए एस.आई.आई को एकाधिकार सौंपने के लिए एक रिश्वत थी?

जब यूनाइटेड किंगडम (यू.के) निर्मित वैक्सीन की पेशकश सीधे भारत को ही की गई थी, न कि किसी विशेष दवा कंपनी को, तो सिर्फ़ एस.आई.आई को वैक्सीन बेचने की अनुमति किसने दी ?

हमें यह भी पूछने की जरूरत है कि एस.आई.आई के कोविड-19 वैक्सीन बेचने के एकाधिकार को तोड़ने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? टीकों के प्रभावी और तेजी से वितरण के लिए वैक्सीन के विकेंद्रीकृत करने पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

गौरतलब है कि, फार्मास्युटिकल दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने 4 साल बाद पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड वैक्सीन दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। इस आलोक में यह उल्लेखनीय है कि कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई और इसका निर्माण भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया और भारत मे इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।

भारत उन देशों में से एक है, जिसने वैश्विक स्तर पर 30 करोड़ से अधिक टीके लगाने के बावजूद, अपने नागरिकों या लाभार्थी देशों के नागरिकों पर टीकाकरण के बाद के प्रभावों के संबंध में कोई गंभीर जांच या अध्ययन नहीं किया है।

दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान: कम ज्ञात बातें

'कोविड-19 के दौरान मुझे राशन देने से मना कर दिया गया क्योंकि मैंने टीका नहीं लगवाया था। राशन पाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया था'

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार,
भारत में टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं (AEFI) के

89,231 मामले

सामने आये है ।

- **कोविशील्ड के कारण 63,315**
- **कोवैक्सिन के कारण 6,757**
- **स्पुतनिक के कारण 30**
- **1,148 मौतें (कोविशील्ड के कारण 921 और कोवैक्सिन के कारण 92)**

उत्तर प्रदेश के प्रणव ने बताया, 'कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद मेरे पड़ोसी की मौत हो गई। अधिकारियों ने हमें वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर किया। हमें यह भी नहीं पता कि हमें कौन सी वैक्सीन दी गई थी।'

संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीकाकरण के बाद 1,148 लोगों की मृत्यु हुई है। यह आँकड़ा वास्विकता से कई गुना कम है क्योंकि इस सरकार की मूल प्रवृत्ति ही आँकडें छुपाना है ।

दो अलग-अलग आर.टी.आई दाखिल करने पर हमें पता चला कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद कुल 27 मौतें हुईं

7 मामलों का कोविड-19 टीकाकरण से अप्रत्यक्ष संबंध था

अगर प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्ट करने की कोई व्यवस्था होती तो ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी

इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मौतों की संख्या सही है। ऐसी कई मौतें छूट गई होंगी और कम रिपोर्ट की गई होंगी।

भारत में कौन अधिक अमीर हुआ और किसकी आय कई गुना बढ़ गई, किसने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया, यह भारत की आर्थिक वृद्धि के विश्लेषण में महत्वपूर्ण है। महामारी के दौर में ही भारत ने दुनिया भर में 39 अरबपतियों का योगदान दिया। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी सहित शीर्ष पर मौजूद लोगों की संपत्ति में इस दौरान 1000% से अधिक की वृद्धि हुई।

तो, हमेशा आंखों पर पट्टी बांधे रहने वाले मतदाता को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई गारंटी वास्तव में क्या हैं?

- कई मुस्लिम तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार किया गया और बिना किसी मुकदमे के कई दिनों और महीनों तक जेल में रखा गया।
- अप्रैल 2021 में, एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को कई पोस्ट हटाने और विभिन्न खातों को ब्लॉक करने के लिए नोटिस भेजा, जो महामारी और उसके प्रबंधन पर चर्चा कर रहे थे।
- 23 अप्रैल को, भारत सरकार के आदेश पर, ट्विटर (एक्स) ने राजनेताओं, फिल्म निर्माताओं और महामारी से निपटने की आलोचना करने वाले अन्य लोगों के 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया।
- **सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफार्मों पर सूचनाओं को अवरुद्ध कर दिया गया था।**
- 2021 में भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश में, एक व्यक्ति को अपने मरते हुए दादा के लिए ऑक्सीजन की मांग करने वाले ट्वीट पर अधिकारियों द्वारा आरोपित किया गया। उन्होंने उस पर "अफवाह फैलाने" का आरोप लगाया, जबकि अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि व्यापक रूप से ऑक्सीजन की कमी थी।

सन्दर्भ (जुमले नहीं, स्रोत हैं!)

1. https://www.thehindu.com/news/national/railways-to-run-shramik-special-trains-to-move-migrant-workers-other-stranded-persons/article31481996.ece
2. https://www.india.com/health/23-crore-indians-pushed-below-poverty-line-amid-covid-19-pandemic-says-study-4643931/
3. https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/shreyansh-mangla/impact-of-covid-19-on-indian-economy-2-35042/
4. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/70-of-senior-citizens-didn-t-have-healthcare-access-during-covid-survey-122070900542_1.html
5. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-scientists-say-india-government-ignored-warnings-amid-coronavirus-2021-05-01/
6. https://timesofindia.indiatimes.com/india/community-transmission-explained-is-india-in-stage-3-of-covid-19/articleshow/76837244.cms
7. https://www.downtoearth.org.in/news/health/refrain-from-religious-profiling-of-covid-19-cases-who-in-context-of-tabligh-70262
8. https://www.downtoearth.org.in/news/health/refrain-from-religious-profiling-of-covid-19-cases-who-in-context-of-tabligh-70262
9. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37739/9781464818936.pdf
10. https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=warticle&dt=2020050508222
11. https://www.thehindu.com/news/national/oxfam-study-shows-rich-got-richer-during-pandemic/article61737087.ece
12. https://www.thehindu.com/business/Economy/indias-gdp-grows-16-in-january-march-shrinks-73-in-2020-21/article34690310.ece
13. https://www.thehindu.com/business/indias-unemployment-rate-rises-to-2711-amid-covid-19-crisis-cmie/article61660838.ece
14. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/230-million-indians-pushed-into-poverty-amid-covid-19-pandemic-report-121050600751_1.html
15. https://www.hlrn.org.in/documents/Forced_Evictions_2021.pdf
16. https://www.hindustantimes.com/india-news/crimes-against-dalits-tribals-increased-in-covid-pandemic-year-ncrb-101631731260293.html
17. https://www.aljazeera.com/economy/2020/3/30/migrants-in-india-sprayed-with-disinfectant-to-fight-coronavirus#:~:text=Footage%20showed%20a%20group%20of,on%20social%20media%20on%20Monday.
18. https://theprint.in/india/55-people-feared-police-would-beat-them-during-lockdown-but-trust-has-grown-now-says-survey/716603/
19. https://www.narendramodi.in/prime-minister-narendra-modi-attends-a-public-meeting-in-damoh-madhya-pradesh-581616
20. https://thewire.in/health/who-india-excess-covid-deaths-10-times
21. https://frontline.thehindu.com/covid-19/central-government-rejects-whos-estimate-of-india-covid-deaths/article38491948.ece

22. https://www.youtube.com/watch?v=W5jzuE866lo
23. https://twitter.com/COVIDNewsByMIB/status/1383312316297474049
24. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/02/01/962821038/the-mystery-of-indias-plummeting-covid-19-cases
25. https://thewire.in/government/pm-modi-a-super-spreader-responsible-for-covid-second-wave-imas-navjot-dahiya
26. https://www.theguardian.com/world/2021/may/30/kumbh-mela-how-a-superspreader-festival-seeded-covid-across-india
27. https://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/covid-2nd-wave-situation-going-from-bad-to-worse-says-v-k-paul/81770468
28. https://www.aninews.in/news/national/general-news/kumbh-might-become-covid-19-super-spreader-central-govt-official-expresses-apprehension-at-review-meet20210406142730/
29. https://covidtruths.in/wp-content/uploads/2024/02/Perils-of-Pandemic-Unheard-stories-from-the-streets.pdf
30. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624661
31. https://caravanmagazine.in/politics/narendra-modi-atmanirbhar-bharat-rss-hindu-economics-rashtra
32. https://www.firstpost.com/india/how-will-the-atmanirbhar-bharat-scheme-benefit-the-urban-poor-when-its-long-term-vision-discounts-vital-short-term-measures-8626901.html
33. https://www.thehindu.com/news/national/my-focus-is-on-welfare-of-the-nation-says-modi/article67951300.ece
34. https://www.theindiaforum.in/forum/overcharging-during-pandemic-private-hospitals-maharashtra
35. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/profiteering-during-a-pandemic/article32262912.ece
36. https://covidtruths.in/wp-content/uploads/2024/02/Shambolic-governance.-Unfiltered-loot-The-story-of-pandemic-governance-in-the-national-capital-documented-through-government-notifications-and-peoples-stories.pdf
37. https://www.bjp.org/bjp-manifesto-2024
38. https://qz.com/india/2003124/india-censored-100-covid-19-posts-on-twitter-facebook-this-week
39. https://thewire.in/tech/as-covid-19-crisis-deepens-twitter-takes-down-tweets-criticising-modi-government
40. https://www.aljazeera.com/news/2021/5/5/crime-against-humanity-indias-modi-slammed-for-covid-handling
41. https://www.business-humanrights.org/en/blog/covid-19-in-india-an-excuse-to-dilute-environmental-policy-to-benefit-businesses/
42. https://www.thehindu.com/news/national/narendra-modi-launches-auction-process-for-41-coal-blocks-for-commercial-mining/article31858048.ece
43. https://scroll.in/article/1036361/how-india-failed-those-who-were-harmed-by-the-covid-19-vaccine

यहां प्रस्तुत सभी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और समाचार लेखों पर आधारित हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रस्तुत डेटा हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी (एच.जे.ए.सी) और पीपुल्स कमीशन और सार्वजनिक जांच समितियों द्वारा सहयोगात्मक रूप से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई से प्राप्त किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं के विश्लेषण का डेटा “शैम्बोलिक गवर्नेंस; अनफ़िल्टर्ड लूट - राष्ट्रीय राजधानी में महामारी शासन की कहानी” से लिया गया है ।

Peoples' Commission and Public Inquiry Committee

Email: **peoplescommission2021@gmail.com** | Website: **covidtruths.in**
Instagram: **@covidtruths** | Twitter: **@covid_truths**